एकता परिषद राहत अभियान

09-16 जून 2020 संस्करण क्रमांक -14

संपादकीय

अपनी धरती अपना पानी, मिलजुल करें सब खेती किसानी ।

कोविड 19 की महामारी से निबटने के लिए पूरी दुनियां में मानव मानव के बीच दूरी, मास्क के उपयोग को आदतों में बदलने, स्वच्छता और साफ सफाई के साथ सात्विक भोजन को अपनाने के उपायों को सबसे कारगर उपायों के रूप में माना है। इसलिए दुनियां के कई देशों ने लॉक डाउन को एक सटीक कदम के रूप में स्वीकार किया ताकि कम से कम लोग घर से बाहर न निकलें और संक्रमण के फैलाव पर अंकुश लग सकें।

निश्चित रूप से कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए भारत में भी इस सदी के सबसे लंबे समय का लॉक डाउन लगाया गया तथा इसके सार्थक परिणाम भी सामने आए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पूरा देश कोरोना महामारी के बारे में जाग्रत हो गया जिसकी बजह से रोजमर्रा के जीवन चक्र में भी होने वाले सुधार और परिवर्तन भी सामान्य जीवन मे परिलक्षित हो रहे हैं।

कोरोना संकट से प्रभावित प्रवासी मजदूरों की वाहर से वापसी के बाद, बड़ी संख्या में घर लोटे श्रमिकों को कैसे काम के साथ जोड़ा जाए यह समाज और सरकार दोनों के लिए बड़ी चुनौती है ।

एकता परिषद एक गांधीवादी जन संगठन है जिनके प्रशिक्षण में ही श्रमदान एक विषय है। इसलिए **'श्रमदान से समाधान'** अभियान के साथ गांव के जनसरोकार के कामों तथा संरचनाओं को समुदाय द्वारा सामूहिक श्रम से निर्मित करने के अभियान में प्रवास या पलायन से गांव वापस लोटे श्रमिकों को जोड़ने का एक बृहद अभियान शुरु किया है। श्रमदान अभियान के पूरे देश से उत्साहित करने वाले अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें जहां एक तरफ समुदाय के लोगों की निर्मित की जाने वाली संरचनाओं के प्रति स्वामित्व की भावना पैदा होती है वहीं दूसरी तरफ जब एक साथ पूरा परिवार काम करता है तब अपनत्व एवं भाई चारे की भावना मजबूत होती है। इसीलिए महात्मा गांधी ने समाज और देश के निर्माण में श्रमदान को एक जीवनचर्या के रूप में अपनाया था तथा गांधी जी के आश्रम से श्रमदान की प्रेरणा लेकर लाखों लोगों की दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन देखने के अनुभव हुए थे। देश में लॉक डाउन एवं कोरोना महामारी की इस बिषम स्थिति में जब पलायन से सभी लोग घर वापस आ गए हैं तब एकता परिषद ने देश के 12 राज्यों के 59 जिलों में एक साथ श्रमदान के अभियान चलाकर 10000 से अधिक श्रमिकों के माध्यम से 75 से अधिक जल संरचनाओं के निर्माण का काम सामूहिक श्रम से प्रारंभ किया है। अभी तक एक लाख से अधिक श्रम दिवस का काम हो चुका है तथा दो दर्जन से अधिक जल संरचनाएं पूर्ण हो चुकी हैं ।

श्रम शक्ति से समाज के निर्माण का यह अद्भुत प्रयोग सफलता का इतिहास लिख रहा है। आओ हम सब मिल कर टिकाऊ विकास की आधारशिला के अग्रिम पंक्ति के विकास के वाहक बनें जिससे आगे भविष्य में आजीविका के लिए किसी को पलायन नहीं करना पड़े ।

श्रमदान महादान, श्रमशक्ति महाशक्ति ।

गिरते हुये भूमि जल स्तर को बढ़ाने एकता परिषद की पहल।

एकता परिषद ने 44 जिलों में शुरु किये जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य।

3135 प्रवासी श्रमिको को मिला 11155 कार्य दिवस का काम।

90 से 95 लाख लीटर अतिरिक्त जल भंडारण की संम्भावना

रबीन्द्र सक्सैना, ग्वालियर

देश में सूख रहे जलस्रोत और गिरते हुये भूजल स्तर को बचाये रखने के लिये एकता परिषद कई वर्षों से जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य कर रही है। इसी कड़ी में एकता परिषद ने 4 राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंव उड़ीसा के 44 जिलों मे जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य के लिये श्रमदान शिविरों का आयोजन 2 जून 2020 से प्रारम्भ किया। यह श्रम शिविर European Union-Whh India **एंव प्रयोग समाज सेवी संस्था तिल्दा** के सहयोग से सभी 4 राज्यों में किये गये। इन श्रमदान शिविरों के माध्यम से कोविड -19 के कारण अपनी आजीविका और आय से प्रभावित 3155 प्रवासी श्रमिको के लिये 11155 कार्य दिवस का कार्य देने में सफलता रही है। सभी श्रमदान शिविरों को प्रारम्भ करने से पहले कार्य स्थल पर क्या-क्या सावधानी रखना है एवं कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय सभी को बताये गये। श्रमदान के बदले प्रत्येक श्रमिक को 15 दिन की भोजन सामग्री **"सम्मान राशन किट"** प्रदान की गई जिसमें आटा/चावल, दाल, तेल, मसाले, नमक, साबुन और आलू, प्याज आदि दिये गये। यह सभी वह स्थानीय श्रमिक थे जो चैत्र माह में फसल कटाई के लिये अन्य राज्यों में परिवार सहित पलायन कर जाते हैं और बदले में इन्हे 3 से 4 माह के लिये अनाज और कुछ राशि मिल

जाती है जिससे यह चोमासा काट लेते हैं लेकिन इस वर्ष कोरोना में हुये लॉकडाउन के कारण कुछ भी नही मिला और जो जमा पूजी थी आने जाने में खर्च कर दी।

जैसा कि विदित है कि एकता परिषद वंचितों के **जल, जंगल और जमीन** पर अधिकार और उनकी आजीविका की सुनिश्चितता को लेकर पिछले 2 दशक से जन पैरवी का कार्य कर रही है। जनादेश 2007 आंदोलन के बाद आये वन

अधिकार कानून के बाद कई राज्यों में आदिवासियों को जमीन दिलाने में सफल रही है।

एकता परिषद का दूसरा अभियान आदिवासियों को मिली जमीनों का समतलीकरण, मेड़वंधी के साथ–साथ सूखी व बंजर जमीन के लिये भू–गर्भ जल स्तर नीचे न खिसके इसके लिये गॉव में ही जल संरक्षण एवं संवर्धन के कई प्रकार के काम कर रही है। इसी श्रृखंला में खेतों को जाड़ने वाले छोटे नालों की खुदाई व सफाई, तालाबों का गहरी करण, चेक डेम व स्टॉप डेम निर्माण, गॉव में बंद पड़े कुओं की सफाई एंव नये कुओं की खुदाई जैसे काम किये जा रहे हैं।

एकता परिषद का मुख्य उद्धेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन और छोटे तालाबों में जल भंडारण कर कृषि उपयोग में लेना और फसल पैदावार को बढ़ाना है।

राज्यवार विश्लेषण –

1 मध्यप्रदेश – मध्यप्रदेश राज्य के 17 जिलों के 41 गॉव में श्रम शिविर के माध्यम से जल संरक्षण एवं संवर्धन के कई प्रकार की संरचनाओं के काम किये किये गये। जिसके माध्यम से 1275 श्रमिको को 3825 कार्य दिवस का रोजगार मिला । 8 गॉव में जमीनों का समतली करण, 13 गॉव में तालाबों का गहरीकरण,12 गॉव में स्टॉप डेम, 7 गॉव में छोटे नालों, नरुआ का निर्माण और 1 गॉव में कुआ निर्माण का कार्य किया गया है।

2. छत्तीसगढ़ – छत्तीसगढ़ राज्य में 13 जिलों में श्रम शिविर चलाये गये। जिसमें तालाब गहरीकरण ओर उसके पुनरुथान के कार्य मुख्य रहे। कार्य क्षेत्र के 33 गॉव में श्रम शिविर के माध्यम से 970 श्रमिको को 4260 कार्य दिवस का रोजगार दिया गया। यहा सभी शिविर 4 से 5 दिन के लगाये गये। श्रम शिविर के माध्यम से 19 तालाबों, 4 चेक डेम, 1 नाला और 2 कुओं को पुनर्जीवित किया गया।

झारखंड – झारखंड राज्य के पांच जिलों पलामू, हजारीबाग, धनवाद, कोडरमा और चतरा के 14 गांव में श्रमदान शिविरों का आयोजन हुआ जिसमें 400 श्रमिको को 1600 कार्य दिवस का रोजगार दिया गया। 4 दिवसीय शिविरों के माध्यम से 09 तालाबों का गहरीकरण, 1 पानी रोकने का स्टाप डेम, 1 नाला बंधान के साथ–साथ 1 कुआ निर्माण किया गया।

उड़ीसा – इसा प्रकार उड़ीसा राज्य के 9 जिलों के 24 गॉव में श्रम शिविर के माध्यम से जल संरक्षण एवं संवर्धन के कई प्रकार की संरचनाओं काम हुआ। श्रमदान शिविर के माध्यम से 490 श्रमिको को 1470 कार्य दिवस का रोजगार दिया गया । 13 गॉव में तालाबों का गहरीकरण, 1 स्टॉप डेम, 2 छोटे नालों, नरुआ का निर्माण और 1 गॉव में कुआ निर्माण कार्य किया गया है।

इस प्रकार श्रमदान शिविरों के माध्यम से 54 तालाबों का नवीनीकरण, 18 चेक डेम निर्माण, 11 छोटे नाले और पोखर जिनके माध्यम से खेत तक पानी जाता है और 5 कुओं को पुनर्जीवित किया गया है। एक अनुमान के अनुसार अंचल में अच्छी वारिश होती है तो इन संरचनाओं के माध्यम से 90 से 95 लाख लीटर जल के अतरिक्त भंडारण की संभावना है।

क	राज्य	मध्यप्रदेश	छत्तीसगढ़	झारखंड	उड़ीसा	कुल
1	जिला संख्या	17	13	5	9	44
2	गॉव संख्या	41	33	14	24	112
3	श्रमिक संख्या	1275	970	400	490	3135
4	कार्य दिवस	3825	4260	1600	1470	11155
	जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यो की संख्या					
5	तालाबों का गहरीकरण	13	19	9	13	54
6	चेक डेम/स्टॉप डेम	12	4	1	1	18
7	छोटे नाले, पोखर	7	1	1	2	11
8	कुआ निर्माण	1	2	1	1	5

श्रमदान के बदले "सम्मान राशन किट का वितरण"

(चावल/आटा,दाल,तेल,मसाले,साबुन और मास्क)

छत्तीसगढ़

मध्यप्रदेश

ओड़िसा

काम के बदले अनाज योजना के तहत गुन्नीपुरा तालाब की कराई मरम्मत

तालाब पर तीन दिन काम करने वाले 65 मजदूरों को एकता परिषद ने दिया 15 दिन का राशन

भास्कर संवाददाता | श्योपुर

राशन लेकर अपने घरों की ओर जाते मजदूर।

विजयपुर विकास खंड की गुन्नीपुरा ग्राम पंचायत में एकता परिषद संगठन द्वारा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत 20 साल पुराने तालाब की मरम्मत का काम शनिवार को पूरा कराया गया।

11 जून को प्रारंभ तालाब की मरम्मत के इस काम में दूसरे राज्यों से वापस लौटे 65 स्थानीय मजदूरों मजदूरों को 15 दिन का सूखा राशन वितरित किया गया। एकता परिषद के संभागीय अध्यक्ष रामदत्त सिंह तोमर ने बताया कि 20साल पुराना यह तालाब फूटने के कारण अनुपयोगी हालत में था। परिषद ने तीन दिन तक 65मजदूर लगाकर मरम्मत करवाई। इस कार्य श्रमदान भी किया। तालाब की दुरुस्त होने से अब बारिश का पानी संचित हो सकेगा। इससे आसपास के पट्टाधारी किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मरम्मत का काम पूरा होने पर शनिवार को सोशल डिस्टेंस के साथ सभी मजदूर परिवारों के लिए राशन

प्रयोग व एकता परिषद ने सूखा राशन सामग्री वितरण किया

पायनियर संवाददाता ‹ तिल्दा नेवरा

साह, उपसरपंच भनेशवर रोजगार लोगों को सखा राशन वितरण किया

तीस साल से टूटे बांध को जोड़ने के संकल्प के साथ गुना जिले के नोनेरा गांव के 75 परिवार।

स्रोत – सूरज आदिवासी,गुना।

600 बीघा जमीन होगी सिंचित,
एक हजार पशुओं को मिलेगा पीने का पानी,
दो दर्जन कुएं होंगे रिचार्ज।

गुना। मध्यप्रदेश के गुना जिले का बम्बूरी बिकास खंड अत्यंत पिछड़ा हुआ बिकास खंड क्षेत्र में आता है। यहां की कुल आबादी में 32 प्रतिशत आबादी सहरिया आदिवासियों की है। इसी विकास खंड के अंतर्गत नोनेरा गांव है, जिसमे 125 आदिवासी परिवार रहते है। 75 परिवारों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन है, लेकिन ये पूरी जमीन असिंचित है। इसलिए पूरी खेती बाड़ी बारिष पर ही निर्भर है।

प्रति वर्ष लगभग 75 प्रतिशत आदिवासी परिवार आजीविका के लिए यहां से पलायन करते हैं । इस वर्ष भी यहां के लगभग सभी लोगों ने पलायन किया और राजस्थान में फसल कटाई की मजदूरी करने चले गए थे। लेकिन देश में लॉक डाउन होने से इनको जल्दी वापिस घर आना पड़ा और खाली हाथ वापस लोट आये।

एकता परिषद ने दिलाया सहयोग और हिम्मत का भरोसा

अब 6 महीने की इनकी आजीविका प्रभावित हुई है।

पलायन पर गए आदिवासियों की तलाश में एकता परिषद के जिला संयोजक सूरज सहरिया जब गांव में गये तब गांव के मुद्दों की चर्चा हुई कि कैसे प्रति वर्ष यहा से होने वाले पलायन को रोका जाए। आपसी चर्चा के बाद गांव के लोगों ने कहा कि यदि हमारा 30 साल से टूटा हुआ बाँध जुड़ जाए तो पूरे गांव को यहीं काम मिल जाएगा और उसी समय गांव के सभी लोगो ने श्रमदान करने का संकल्प लिया। यद्यपि एकता परिषद संगठन ने इन्हें 15 दिन का राशन उपलब्ध कराने का वायदा किया है। बॉध पर 15 दिन तक कुल 750 कार्य दिवस काम होगा। काम प्रारम्भ हो चुका है और तुरंत काम शुरू होने से गांव में खुशी का माहौल है।

एकता परिषद के सूरज आदिवासी ने बताया कि पूरे जिले में इस काम का प्रभाव होगा, संगठन के प्रति विश्वास बढ़ेगा। 600 बीघा जमीन होगी सिंचित, एक हजार पशुओं को पीने का पान मिलेगा, दो दर्जन कुएं रिचार्ज हो जायेगें। लोगों को तैयार करने में राजाराम आदिवासी, भारत आदिवासी का भी विशेष योगदान रहा ।

पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण अभियान

विश्व पर्यावरण दिवस पर एकता परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया पौध-रोपण। 5000 पौध-रोपण कर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश।

स्त्रोत - करोना समूह।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई राज्यों में एकता परिषद संगठन के कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर समुदाय को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना तेलंगाना टीम ने एकता परिषद के साथ मिलकर 500 पौधों का रोपण किया। मध्यप्रदेश के श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, सागर, दमोह, कटनी और टीकमगढ़ में 1800 छायादार और फलदार पौधे लगाये गये। छत्तीसगढ़ की जिला संयोजिका नुरानी जैन एंव के नेतृत्व में ग्राम भैंसादादर के युवा संगठन के माध्यम से 200 फलदार वृक्ष रोपण किया गया । जिलर संयोजिका श्रीमति मीना वर्मा ने बताया कि रायपुर जिले व गरियाबंद जिले के 50 गाँव में इस साल 50 हजार पेड़ लगाने की योजना बनाई गई हैं ।

सागर जिले के दीपक भाई का कहना है कि लोगों को पार्यावरण के प्रति जागरूक करना और क्षेत्र में शुद्ध वातावरण बनाकर आने वाले पीढ़ी को सचेत करना तथा हर व्यक्ति अपने घर एवं बाड़ी मे ज्यादा से ज्यादा पौधा रोपण कर जल स्तर को बढ़ाने लोगों को जागरूक किया जा रहा है । टीकमगढ़ की जिला संयोजिका अनुभा जी का कहना है कि लोगों को पर्यावरण के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि जिस तरह हम अपने बच्चों का संरक्षण और उसकी देखभाल करते हैं वैसे ही हमें पेड़ पौधों की देख भाल करना चाहिए तभी हम पार्यावरण को सतुंलन बना सकते हैं। उपस्थित सभी वर्ग की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहां गया कि हम अपनी जिम्मेदारी को सामूहिकता के साथ निभाने का संकल्प लें। कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आस पास वृक्षारोपण करना है ताकि हम अपने आस पास वातावरण को स्वच्छ रख सकें । उपस्थित सभी लोगों ने पेड़ लगाने एवं बचाने का संकल्प लिया।

जैविक खेती प्रोत्साहन अभियान

देशी बीज वितरण कर किया जा रहा आदिवासी किसानों का सहयोग।

स्रोत–कोरोना समूह।

एकता परिषद बुन्देलखण्ड और मानव जीवन विकास समिति कटनी जैविक खेती को प्रोत्साहन देते हुये देशी बीज का वितरण गरीब आदिवासी किसानों को कर रही है। समिति सचिव व एकता परिषद के राष्ट्रीय सदस्य श्री निर्भय सिंह जी ने बताया कि ब्लॉक तेदूखेडा, जबेरा में आदिवासी किसानों के लिए अनाज बीज उपलब्ध कराया जा रहा हैऔर जैविक खेती के लिये आवश्यक जानकारी दी जा रही है। अभी तक ज्वार, कोछों, कुट्की, देशी मक्का और देशी उड़द के बीज उपलब्ध कराले गये है।

जिलाधीश ने झंडी दिखाकर किया कोरोना जागरुकता रथ रवाना

स्रोत–शबनम अफगानी, श्योपुर

जिला–श्योपुर।

श्योपुर जिला अनलोक होने के बाद से जिले मे कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है इसका मुख्य कारण लोगो मे इस महामारी के प्रति जागरुकता की कमी है। एकता परिषद श्योपुर एंव महात्मा गाँधी सेवा आश्रम के द्वारा निकाले जा रहे इस कोरोना जागरुकता रथ के माध्यम से जहाँ लोगो को इस बीमारी से बचाव के लिये मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस बनाने तथा साबुन से हाथ धोने के बारे मे जागरुक किया जायेगा वही बच्चो को सुपोषित रखने के लिये उन्हे गुड़ व सत्तू का वितरण भी किया जायेगा यह उदगार श्योपुर के जिलाधीश आर के श्रीवास्तव ने महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा कराहल क्षेत्र के लिये निकाले गये कोरोना जागरुकता रथ को हरी झंडी दिखाते समय व्यक्त किये। उन्होने कहा महात्मा गांधी सेवा आश्रम इस दिशा मे उल्लेखनीय कार्य कर रहा है जिसके लिये वह प्रशंसा का पात्र है उनका कहना था की श्योपुर तहसील मे भी कोरोना संक्रमण बड रहा है वहां भी लोगों को इस बीमारी से बचाव के लिये जागरुक किया जायेगा।

पोषण समृद्धि योजना रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

रथ को हरी झंडी दिखाते अधिकारी। ● नईदुनिया

श्योपुर। (नईदुनिया प्रतिनिधि)। महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित परियोजना पोषण समृद्धि योजना रथ मंगलवार को रवाना हुआ। रथ को कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह रथ लोगों को जगरूक करने के लिए गांव-गांव जाकर संदेश दिया जाएगा।

परियोजना द्वारा तैयार किया गया रथ लोगों के बीच पहुंचकर कोरोना महामारी से बचाव व सावधनी के लिए संदेश दिया शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए समझाइश दी जाएगी। इस कार्यक्रम को लीड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट शबनम अफगानी द्वारा किया जा रहा है। जागरूकता रथ के साथ नीरज श्रीवास्तव, संदीप भार्गव, प्रशांत ग्रामीणों को जानकारी देंगे। रथ को झंडी दिखाते समय सहायक कलेक्टर नवजीवन विजय, एसडीएम रूपेश उपाध्याय, तहसीलदार राघवेंद्र कुशवाह, महात्मा गांधी सेवा आश्रम के प्रबंधक जयसिंह जादौन, समाजसेवी

श्रमदान शिविरों में जाकर बता रहे कारोना से बचने के उपाय

स्रोत–कोरोना समूह

एकता परिषद और प्रयोग समाज सेवी संस्था द्वारा चलाये जा रहे श्रमदान शिविर के माध्यम से **"करोना से सावधानी ही है बचाव"** जागरुकता का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार की जागरुकता मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा के सभी 44 जिलों के 112 गॉवों में चलाये जा रहे है।

सभी श्रमिकों को श्रमदान से पूर्व जानकार दी जा रही है जिसमें उन्हे, आपस में कम से कम एक मीटर की दूरी, अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना, चेहरे पर मास्क लगाना, और सार्वजनिक स्थान पर न थूकना बताया जा रहा है।

इसके अलावा –

- श्रमदान शिविरों के माध्यम से अभी तक 4000 श्रमिक परिवारों तक कोरोना से सावधानी की जानकारी दी गई है।
- सभी श्रमिको को 4000 मास्क वितरण किये गये हैं।
- बार बार हाथ धोने के लिये 2–2 साबुन दिये गये हैं।

स्त्रोत – कोरोना समूह।

66 परिवारों को दी गई राहत राशन किट

एकता परिषद ब्लाक बुदनी जिला सिहोर में प्रवासी मजदूरों, निराश्रित महिलाओ और दिव्यांगों को महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा के सहयोग से सुखा राशन वितरण किया गया। एकता परिषद ब्लाक अध्यक्ष मंन्सुर भिलाला, जिला संमन्वयक राकेश रतन सिंह, महिला मंच कि शकिला बानो, के हाथो से राशन वितरण किया गया साथ गांव वासियो को मास्क लगाने, हाथ साबुन से धोने, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से दुरी बनाने कि लिए बताया गया। खटपुरा, सेमरी, बोरी के महिला पुरूष को राशन प्राप्त होने पर एकता परिषद का आभार व्यक्त किया।

घर जाकर की कैलाश आदिवासी की मदद।

कराहल। एकता परिषद कार्यकर्ता ज्योति रजक अपने क्षेत्र भ्रमण कर रही थी, उसी समय उनकी भेंट ग्राम पाण्डोला में आदिवासी बस्ती कैलाश आदिवासी से हुई और वह उसके साथ कैलाश के घर पहॅच गई। देखा कि कारोना संकट में कैलाश आदिवासी की घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कैलाश का पैर ठीक नहीं हो पा रहा है उसकी पत्नी भी बीमारी के कारण मजदूरी करने नहीं जा पा रही है खाने को भी घर में कुछ नहीं । जब उनसे पूछा गया आज खाने में क्या बनाया है तो उन्होंने बताया कि रोटी ही बनाई हैं सब्जी के बारे में पूछना चाहा तो उन्होंने बताया की सब्जी के लिए पैसे नहीं थे इसलिए कुछ नहीं बनाया है। आटा भी दो दिन लायक है। ज्योति रजक के ने स्वयं के व्यय पर खाद्यसामग्री की एक किट तैयार करवाई गई जिसमें 10 किलो आटा 1 किलो दाल 1 किलो शक्कर तेल और मसाले नमक सहित पूरी किट उसको घर जा कर दी। तन ढकने के लिए परिवार को कपड़े भी दिए गए , साथ जब उनसे पूछा गया कि आपने इस पैर को दिखाने के लिए तो फिर क्यों नहीं गए तो उन्होंने बताया कि जाने की व्यवस्था नहीं है किराया भी नहीं है तो फिर कैलाश को किराया खर्चे के लिए ₹500 भी दिए जिसके बाद उसके चेहरे पर खुशी स्पष्ट दिख रही थी। उस परिबार में 3 माह का बच्चा भी हैं जो बहुत कमजोर हैं माध्यम कुपोषित की श्रेणी में आ रहा है। मॉ को बताया गया कि वो खुद भरपेट भोजन खाये ताकि 3 माह के बच्चे को स्तनपान कर सके। राशन, कपड़ा और रुपये पाकर उसने खुशी जाहिर की और उसने धन्यवाद भी दिया। जब सेकेट्री से बात की गई तो उसके द्वारा कहा गया कि विकलांगता सर्टिफिकेट नही बन सकता क्योंकि बो सिर्फ घाव हैं मजदूरी के लिए बाहर गया नही इस कारण से अप्रवासी पंजीयन नही किया जा रहा हैं।

कोरेना संकट काल में सुपोषण अभियान

एकता परिषद के द्वारा कुपोषित बच्चों को सत्तू एवं गुड़ किया वितरण

श्री रामदत्त सिंह तोमर, विजयपुर

एकता परिषद के सम्भागीय समन्वयक रामदत्त सिंह तोमर ने बताया है कि कोरोना महामारी की मार झेल रहे प्रवासी श्रमिको के आगनवाडी में दर्ज बच्चों को एवं असहाय वृद्ध महिला, पुरुषों को कुपोषण एवं महामारी के संकट की घड़ी में एकता परिषद के द्वारा चेटीखेड़ा, पालपुर, अगरा, हीरापुरा, एवं पैरा की आगनवाडी में दर्ज 79 कुपोषित बच्चों एवं वृद्धो को गाँव मे पहुँच कर 1 किलो सत्तू एवं 400 ग्राम गुड़ के पैकिट थाना प्रभारी अगरा श्री श्यामवीर सिह तोमर एवं सहायक थाना प्रभारी श्री कृष्णवीर कुशवाह जी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के सेक्टर ग्रोथ मोनिटर अखिलेश तोमर , मारुति नंदन अवस्थी , धर्मेश गोयल तथा स्थानीय आंगनवाडी कार्यकर्ता की मौजूदगी में आगनवाडी केंद्र अगरा हीरापुरा में 20 बच्चों को ,पालपुर में 25 , पैरा में 22 और चेटीखेड़ा में 12 बच्चो को तथा 10 असहाय वृद्दो को सत्तू एवं गुड़, सोसल डिस्टेन्स का पालन करते हुए वितरण किया।

समुदाय को कोरोना से बचाव के बारे में समझाइस देते हुये बताया कि बार बार साबुन से हाथ धोते रहे तथा आपसी दूरी को बनाये रखे घर एवं गाँव मे सभी अपने मुंह को मास्क एवं गमछा से बांध कर रहे जिससे कि संक्रमण का खतरा कम रहेगा।यह अभियान किसी शासकीय विभाग का नही है यह आदिवासी एवं दलित बंचितो के बीच बर्षो से कार्य कर रहा संगठन एकता परिषद का है और यह अभियान विजयपुर क्षेत्र में आगे भी चलता रहेगा।

एकता परिषद के द्वारा कुपोषित बच्चों को सत्तू एवं गुड़ किया वितरणः तोमर

श्योपुर।एकता परिषद के सम्भागीय समन्वयक रामदत्त सिंह तोमर ने प्रेस को अवगत कराते हुए बताया कि कोरोना महामारी की मार झेल रहे प्रवासी श्रमिको के आगनवाडी में दर्ज बच्चों को एवं असहाय वृद्ध महिला , पुरुषों को कुपोषण एवं महामारी के संकट की घड़ी में एकता परिषद के द्वारा आज चेटीखेड़ा, पालपुर

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कहां हुई चूक?

40 करोड़ युवाओं के कौशल में विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन...

श्री रमेश शर्मा – राष्ट्रीय समन्वयक,एकता परिषद

कार्टून साभार, विक्रम नायक, एकता परिषद

एक सत्यकथा है। 9 नवम्बर 2014 को एक नये मंत्रालय का जन्म हुआ जिसका मकसद देश के लगभग 65 फीसदी युवाओं को बेहतर भविष्य देने के लिये रोजगार योग्य कौशल सुनिश्चित करना था / है। 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौशल विकास योजना का प्रारूप रखते हुए यह तय हुआ कि हर बरस लगभग एक करोड़ युवाओं को बेहतर रोजगार योग्य कौशल में प्रशिक्षित करके देश के विकास से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (त्त्व्) का आयाम रखते हुये यह माना गया कि उन्हें असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में लाया जाएगा। सत्य यह भी है कि भारत जैसे देश में कौशल मंत्रालय ने बहुत ही कम समय में उम्मीदों की पूरी एक दुनिया खड़ी कर दी है।

आज देश के जो लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार, महामारी और आर्थिक असुरक्षा के मध्य अपने गावों की ओर लौट रहे हैं, उन्हें भी/ही इस सत्यकथा का पात्र होना था। बहरहाल, वे असम से लगभग 3500 किलोमीटर दूर मजदूरी की तलाश में केरल में हैं। बिहार से 1500 किलोमीटर चलकर पंजाब आये युवाओं की आंखों में भी वही सपना है, तेलंगाना से लगभग 1000 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र आए मजदूरों को लगता है कि बेहतर रोजगार की मुट्ठी भर संभावना यहां है, और ओडिशा से गुजरात 2000 किमी. आए हजारों युवाओं ने यह मान लिया है कि अपनें घरों से दूर शायद यहीं वो कुछ कमाकर पूरे परिवार का पेट पाल सकते हैं। इनमें से हर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं था, जिसे कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में जाने-सीखने का अवसर मिलता। यह महज संयोग है कि इनमें से ज्यादातर युवा "कौशल विकास मंत्रालय" के विषय में नहीं जानते,लेकिन यह केवल संयोग नहीं है कि लगभग ये सभी प्रवासी श्रमिक ऐसे किसी भी संभावनाशील मंत्रालय के प्रति गंभीर नहीं हैं।

राहुल मरावी, मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले का युवा है जो इस बरस अपने जिले के लगभग 200 से अधिक युवाओं के साथ रोजगार की तलाश में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक गया। राहुल बताते हैं कि ज्यादातर लोग यहां भवन निर्माण, लोडिंग-अनलोडिंग और छोटी कंपनियों में काम करते हैं। उनका कौशल क्या था ये वो सब पूरी तरह से भूल चुके, रोजगार कार्यालय में कब पंजीयन करवाया था उन्हें यह भी अब याद नहीं। डिंडोरी में कोई प्रतिष्ठान, कौशल विकास केंद्र के रूप में दर्ज है ऐसा कभी उन्होनें सुना ही नहीं है। राहुल और उसके जैसे पलायन करने वाले युवा श्रमिक, यह गहराई से जानते और मानते हैं कि उनकी नियति, सरकार की योजनायें और घोषणाएं नहीं, बल्कि एक ऐसी मजबूरी है जो डिंडोरी के आदिवासी गावों से निकलकर सुदूर महानगरों में एक असुरक्षित भविष्य तलाशनें के लिये उन्हें बाध्य करती है।

झारखण्ड के सिमडेगा जिले की एल्मा एक्का भी उन भाग्यशालियों में नहीं थी, जिन्हें सरकार ने लाखों बेरोजगारों के बीच कौशल केंद्र में कुछ सीखने

समझने का अवसर देती। एल्मा कहती है कि मैं बांस और लकड़ी के कारीगरों के गांव में जनमी और पली बढ़ी। मुझे लगता था कि एक दिन मैं भी इसी काम को आगे बढ़ाते हुए परिवार को पाल-पोस सकूंगी। और फिर हमारे जंगलों में वन विभाग का राज आते ही हम सब वन-अपराधी घोषित कर दिए गए। हमारे अपने बाप-पुरखा के जंगल से बांस और लकड़ी लाने की सजा, सरकार ने मुकर्रर कर दी। हमारा संसाधन और हुनर दोनों छिन गया। पलायन मुझे विरासत में नहीं, बल्कि एक ऐसी मजबूरी की वास्तविकता के रूप में मिली, जिसने मुझे और मुझ जैसे हजारों युवतियों को उनके गांवों से हमेशा-हमेशा के लिए जुदा कर दिया।

बहरहाल यदि आपको डिंडोरी और सिमडेगा में किसी सक्रिय कौशल विकास केंद्र की तलाश है, तो वो पूरी होने पर राहुल और एल्मा जैसे आँखों में सुरक्षित भविष्य का सपना संजोए युवाओं को जरूर बताइए। घोषित किए तंत्र पर उनका जो मरता हुआ भरोसा था वो संभव है किसी सच्ची खबर से पुनः जिंदा हो जाये। लेकिन यदि आपकी तलाश अधूरी है तो यह झूठ कहने का साहस जुटाइये कि समाज और सरकार "उनको" लेकर संवेदनशील है। अच्छा होता, राहुल और एल्मा को सच और हमें झूठ कहने का अवसर न मिला होता।

बुनियादी सवाल यह है कि इस देश को "आत्मनिर्भरता" को प्रोत्साहित करने वाले कौशल संवर्धन का तंत्र चाहिये या "आत्मनिर्भर कौशलकारों और हुनरमंदों" को सम्मान और उन्हें उनका स्थान देने की ईमानदार पहल चाहिए ? मंडला, मुर्शिदाबाद, मधुबनी और मयूरभंज के बरसों से स्थापित बेहतरीन कौशल को खारिज करते हुए लोगों को मशीनों में झोंक देना आखिर कौन सा कौशल संवर्धन है? यदि जांजगीर चाम्पा के बुनकरों से अधिक कीमती, पावर प्लांट के अकुशल मजदूर हैं तो क्या कौशल विकास की नयी परिभाषा नहीं गढ़ी जानी चाहिये? और फिर भागलपुर के हजारों कारीगरों को पंजाब-हरियाणा के ईंट भट्ठों में मजदूरी के लिये धकेल देना आखिर किनकी असफलताओं की जिंदा मिसालें हैं?

वर्ष 2019 में नीति आयोग का सुझाव था कि कौशल विकास की संभावना के मद्देनजर विद्यालयीन शिक्षा को इसका माध्यम बनाया जा सकता है ताकि प्रशिक्षण के लिए आधारभूत संरचना का विस्तार किया जा सके। इसीलिए वर्ष 2017-18 के 2356 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2018-19 के बजट में 3400 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया ताकि वर्ष 2022 तक लगभग 40 करोड़ सक्षम युवाओं को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित किया जा सके। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार अब तक लगभग 2.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अर्थात आगामी ढाई बरस के भीतर लगभग 37.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है।

सूरत के मिल में कार्य करने वाला बिहार का अनिल कुमार, विज्ञान का स्नातक है किन्तु अब मिल में एक साधारण सा सुरक्षा गार्ड है। लगभग यही कहानी बंगाल के दीपनारायण की भी है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा घर पर छोड़ आया और अब इंदौर के कंपनी में माल ढुलाई का हिसाब किताब रखने वाला मुंशी है। मणिपुर की संध्या देवी का हुनर बेहतरीन सूती कपड़े और शॉल बनाना था, लेकिन अब उसकी पहचान दिल्ली में एक और गुमनाम घरेलू कामगार की तरह है। हरियाणा का सुखविंदर भी उन पढ़े लिखे बेरोजगार की कतार में कहीं खड़ा ऊर्जावान युवा था जो अब मुंबई का एक अनाम टैक्सी ड्राइवर है। बहरहाल इनमें से कोई भी वर्ष 2022 की पटकथा का जिंदा पात्र नहीं हो सका और न ही ये सब अब भी अपनी उम्मीदों को फिर जिंदा करने का कोई असाधारण सा सपना पाले हैं।

बेरोजगारों का ये कारवां किसी घोषित अवसर की प्रतीक्षा में खड़ा भी रह सकता था। लेकिन इनमें से हर कोई अपनी पगडंडियां खुद गढ़ने आगे बढ़ गये। आज उनका मुट्ठीभर सपना केवल इतना ही है कि घर-परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सकें। नये भारत के निर्माण के लिये उन 40 करोड़ संभावना शील युवाओं में शामिल न होने की टीस उन सबमें भी है तो जरूर, लेकिन 2022 तक का फासला भी तो कम नहीं।

एकता परिषद्, संसाधन केन्द्र, पुरानी छावनी थाने के पास, ए.बी. रोड पुरानी छावनी ग्वालियर, सम्पर्क & 9993592425
Contact Persons : Ran Singh Parmar 9993592425, Email: mgsa.india@gmail.com ,
www.mahatmagandhisevaashram.org, www.ektaparishad.org